# विदेश राज्य मंत्री थरूर का 'कैटल क्लास'

आजकल सरकार ने महंगाई को लेकर जनता के गुस्से से बचने के लिए मितव्ययिता का ड्रामा शुरू कर रखा है। मंत्रियों से कहा गया है कि वे विमान यात्रा के दौरान इकॉनमी क्लास में ही सफ़र करें। इसका विरोध संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल कुछ नेताओं ने तो किया ही, कांग्रेस के भी कुछ नेता इसके विरोध में नज़र आये। पर आलाकमान सोनिया गांधी और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने इकॉनमी क्लास में यात्रा कर नज़ीर पेश कर दिया। इसके आगे नेतागण मजबूर हो गये। कृषि मंत्री शरद पवार ने जो पहले इकॉनमी क्लास में यात्रा के प्रस्ताव के विरोध में थे, लाचार हो गये। विदेश मंत्री एस एम कृष्णा जिन्होंने तीन माह फाइव-स्टार होटल में रह कर जनता का एक करोड़ रुपया फूंक दिया, यह स्वीकार किया कि वे अब चार्टर्ड विमानों में सफ़र न कर सामान्य यात्री विमानों में यात्रा करेंगे और पैसे की 'बर्बादी' नहीं करेंगे, पर उनके छोटे मंत्री शशि थरूर ने यह कह कर कि इकॉनमी क्लास 'कैटल क्लास' है, यानी उनमें भेड़-बकरियां सफ़र करती हैं, मध्यवर्गीय जनता के प्रति अपनी घृणा को उजागर कर दिया। यह आदमी विदेश राज्य मंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के बाद से ही विदेश मंत्री एस एम कृष्णा की भांति ही फाइव-स्टार होटल में पड़ा हुआ था और अपने रहने, खाने एवं पीने पर आम जनता का एक लाख रुपया प्रतिदिन खर्च कर रहा था। जब एस एम कृष्णा एवं उससे फाइव-स्टार होटल छोड़ कर सरकार द्वारा आंवटित किये गये बंगलों में रहने के लिए कहा गया तो इन दोनों मंत्रियों ने यह घोषणा कर दी कि बंगले जब तक उनके रहने लायक नहीं बन जाते, वे होटल नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह कह कर कि वे अपने पैसे खर्च कर होटल में रह रहे हैं, सरकारी पैसा नहीं खर्च कर रहे, सफ़ेद झूठ बोला। इन दोनों मंत्रियों के बयान के बाद जब आलाकमान ने इन्हें घुड़की पिलाई तो अपनी चमड़ी बचाने के लिए इन्होंने होटल छोड़ा, वरना ये तो जब तक सरकार चलती, होटल को ही आशियाना बनाये रखते। शशि थरूर कोई राजनेता नहीं है। भारतीय विदेश सेवा का यह अधिकारी लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र संघ में बना रहा। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद का चुनाव भी लड़ा और इस तरह विशेष तौर पर चर्चित हुआ। अंग्रेज़ी अखबारों ने इसके लेख और कॉलम आदि छाप कर इसे लेखक का दर्जा भी दे रखा है। पर आम जनता के प्रति इसके मन में कितनी घृणा है, इसका पता इसकी उपरोक्त बयानबाज़ी से चलता है। जब यह हवाई जहाज के इकॉनमी क्लास में सफ़र करने वालों को भेड़-बकरियां मानता है तो ज़मीन पर चलने वालों को तो कीड़े-मकोड़े ही मानता होगा। इस बात को सभी जानते हैं कि हवाई जहाजों में कौन से लोग़ सफ़र करते हैं। अब जबकि विमान सेवा पहले की बनिस्पत सस्ती हुई है, मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के लोग भी गाहे-ब-गाहे विमान यात्रा का सुख पा लेते हैं, पर पहले यह संभव नहीं था। पहले के मुकाबले अब घरेलू उड़ानें भी ज्यादा हो गई हैं। फ़िर जब इसने देख लिया कि सोनिया और प्रणव जैसे नेताओं ने दिखाने के लिए ही सही, इकॉनमी क्लास में यात्रा कर ली है तो उस क्लास का मज़ाक उड़ाने से पहले उसे सोचना चाहिए था। अब इसके ऐसे बयान से विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष में भी नेताओं की भृकुटियां तन गई हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे इस्तीफ़ा तक देने की मांग कर दी है। जनता दल (यूनाइटेड) के नेतागण भी इसे हटाने के पक्ष में हैं। हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है -'इसे हटाओ।' इधर मामला संगीन होता देख कर थरूर ने माफ़ी मांग ली है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा है कि वे तो सिर्फ़ मज़ाक कर रहे थे। आखिर क्यों? फ़िर प्रधानमंत्री उसके पक्ष में सामने क्यों आ रहे हैं? महज़ इसलिए कि अमेरिका का उन पर वरद हस्त है? वजह यह है कि उन्होंने लंबे समय तक वर्ल्ड बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में सेवा कर अमेरिका की चाकरी की है? यही बात अब थरूर के सामने आ रही है। थरूर ने भी अपने कैरियर के कई साल संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का डिप्लोमेट रह कर जम कर अमेरिका की सेवा की है। इसी 'सेवा' से खुश होकर पहले तो अमेरिका ने इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव ही बनाना चाहा ताकि डूब-डूब कर और उतरा-उतरा कर जितना खाना हो खा ले, पर यह बाज़ी हाथ नहीं लगी। अब इसकी सेवा कहां ली जाये, यह समस्या खड़ी हो गई। अमेरिका ने प्रधानमंत्री की दूसरी पारी खेलने जा रहे मनमोहन सिंह को कहा कि इस बंदे को विदेश विभाग में ले ले, काफ़ी काम आयेगा। वैसे राजनीति का अनुभव नहीं है, पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चुनाव लड़ कर चर्चित चेहरों में शुमार हो गया है। इसका ज्यादातर जीवन विदेशों में गुज़रा है, इसलिए यह अपने देश की ज़मीनी सच्चाइयों से वाकिफ़ नहीं होगा और सिर्फ़ इसी वजह से तुम्हारे लिए विशेष काम का होगा। सरदार जी ने सिर हिलाया और कहा-रख लूंगा। इधर अमेरिकी हुक्मरानों ने थरूर के कान में यह मंतर पढ़ दिया कि विदेश विभाग से संबंधित संवेदनशील सूचनायें हमें एडवांस में भेजते रहना और ऐसा करते हुए जरा भी न डरना। इसके बदले जो पगार तू चाहेगा, वह तुझे मिलती रहेगी। जब मनमोहन सिंह ने तय कर लिया कि छोटा विदेश मंत्री इसे ही बनायेंगे तो अमेरिका ने थरूर को डॉलरों की पोटली बांध कर दे दी। और शुभकामनायें भी। फ़िर बैठक कर काम डिटेल में समझाया। उस बैठक में प्रधानमंत्री नहीं थे। कुल मिला कर इसका काम विदेश विभाग में जासूसी करना था और सभी महत्त्वपूर्ण जानकारियां उसे सौंपना था। तीन महीने सत्ता में रहने के दौरान अमेरिका के हित में उसने अच्छा-खासा काम किया होगा। पर अति विलासिता ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इनके क्रिया-कलापों से 'महारानी' भी क्षुब्ध हैं। विरोधी सांसदों के दबाव में आकर कहीं इस्तीफ़ा मांग लिया तो विशुद्ध अभिजातीय और औपनिवेशिक गुलाम मानसिकता वाले थरूर कहीं के नहीं रह जायेंगे। वैसे इस बात की संभावना कम ही है। विरोधी दलों द्वारा इस्तीफ़ा मांगे जाने के बावजूद सरकार इस्तीफ़ा नहीं लेगी। मनमोहन सिंह इतना कड़ा कदम नहीं उठायेंगे और जैसे-तैसे सोनिया को भी मना ही लेंगे। इसीलिए, शशि थरूर जमे रहो। तुम्हारा जन्म देव कुल में हुआ है। फाइव-सेवन स्टार होटलों में रहने-खाने और विशेष विमानों में उड़ने का अभियान जारी रखो। सर्विस विमान से कभी भी न जाना। चार्टर्ड विमानों से उड़ो। भीड़ के बीच रहोगे तो स्वाइन फ्लू होने की आशंका बनी रहेगी। बेफ़िक्र रहो। भारतीय सत्ता में रहते हुए अमेरिका के हित में काम करते रहो। निरंतर आगे बढ़ोगे।

-ग़रीबदास

# नक्सली ईमानदार लोग़ों को नहीं मारते : राज्यपाल, झारखंड

रांची के एक दैनिक 'सन्मार्ग' में छपी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के राज्यपाल के एस नारायणन ने रांची में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि 'नक्सली कभी ईमानदार लोग़ों को नहीं मारते। उनके निशाने पर अक्सर भ्रष्ट व लापरवाह अधिकारी, कर्मचारी होते हैं।' यह कह कर राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में नक्सली कौन हैं और क्या चाहते हैं? उनकी इस बात से यह भी पता चलता है कि आम जनता के बीच नक्सलियों की जो खलनायक और लुटेरों-हत्यारों जैसी छवि बनाई गई है, वह गलत है। जब एक राज्य का महामहिम नक्सिलयों के बारे में ऐसी बात कहे तो इसे हलके में नहीं लिया जा सकता। जाहिर है, महामहिम ने यह कहने के पूर्व काफ़ी सोचा-विचारा व चिंतन-मनन किया होगा। आज पूरा झारखंड माओवादियों की गिरफ़्त में है। वहां के राज्यपाल का यह कहना अपने आप में बहुत मायने रखता है।

गत दिनों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में उग्र वामपंथियों यानी नक्सलियों को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और यह कहा कि इनसे निपटने के लिए पुलिस को कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। उन्होंने इसके सामाजिक पक्ष पर ध्यान देने की जरूरत बतलाई। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने पुलिस समस्या से जुड़ी कई बातें कीं, पर मुख्य मुद्दा नक्सलवादी हिंसा ही रहा। वैसे इस समस्या पर प्रधानमंत्री लगभग प्रत्येक साल ही सम्मेलन करते हैं और पुलिस के आधुनिकीकरण के साथ ही पुरानी रटी-रटी बातें ही दुहराते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी फ़िर से अपनी मांद में जा बैठते हैं और इस बात की पुरजोर कोशिश करते हैं कि कैसे नक्सली हमलों से अपने आप को बचाया जाये।

इधर देखने में यह आ रहा है कि साल-दर-साल नक्सलवादी हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार नक्सलवाद का विस्तार होता चला जा रहा है। अधिक से अधिक राज्य इसके घेरे में आ रहे हैं। अभी 13 राज्यों के सैंकड़ों ज़िले इसकी जद में हैं। जहां नक्सली अपना केंद्र मजबूत कर लेते हैं, वहां राज्य की पुलिस-प्रशासनिक मशीनरी फेल हो जाती है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में लालगढ़। ऐसे न जाने कितने लालगढ़ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री को संभवत: इस बात का अहसास है कि बल-प्रयोग से नक्सली काबू में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके पास भी एक से बढ़ कर एक अति आधुनिक हथियार हैं और वे गुरिल्ला यानी छापामार लड़ाई में सिद्धहस्त हैं। इसीलिए वे सामाजिक पक्ष की बात करते हैं। मनमोहन सिंह को पता है कि ग़रीब जनता जहां नक्सलियों के समर्थन में है , वहीं बुद्धिजीवी माने जाने वाले तत्वों का भी इन्हें नैतिक समर्थन हासिल है। बड़े-बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी भी इनके समर्थक हैं। नक्सलियों के नेता काफ़ी पढ़े-लिखे लोग़ हैं।

नक्सली उन लोग़ों को अपना निशाना नहीं बनाते जो निर्दोष हों अथवा जिन्होंने कभी भी किसी रूप में ग़रीबों का शोषण नहीं किया हो। वे तो बेईमान, भ्रष्ट, तिकड़बाज़ और तरह-तरह से जनता का खून चूसने वाले अधिकारियों को अपना मुख्य दुश्मन मानते है कि वे सरकार की कठपुतली बन कर उनकी हत्या करते हैं। इसलिए आत्मरक्षा में उन्हें पुलिस को मारना पड़ता है। सरकार के पास पुलिस ही दमन का एकमात्र औज़ार है। रांची में नक्सलियों के दमन के लिए राज्य पुलिस के अलावा सीआईएसएफ,बीएसएफ के अलावा नक्सलियों से खास तौर पर लड़ने के लिए गठित की गई कोबरा पुलिस भी शामिल है जिसे ग्रामीणों के विरोध के कारण रहने का ठिकाना भी नहीं मिल पा रहा है। झारखंड हो या बिहार, उड़ीसा हो या आंध्रप्रदेश, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के अफ़सर ही नहीं कर्मचारी भी वहां जाने से घबराते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जब पुलिस के एस नारायणन ने कहा है कि नक्सली कभी भी ईमानदार लोग़ों को नहीं मारते। उनके निशाने पर भ्रष्ट व लापरवाह अधिकारी-कर्मचारी होते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम व पश्चिम बंगाल में भी नक्सली समस्या है, पर वहां विकास का कार्य भी हो रहा है। रोज़गार नहीं मिलने के कारण भी उच्च शिक्षित लड़के नक्सली बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीसी और बीडीओ आदि भी हमीं में से आते हैं। बावजूद इसके धरातल पर योजनायें क्रियान्वित होती दिखाई नहीं पड़ती। नरेगा में काम करने वाली महिलाओं को माह में मुश्किल से तीन-साढ़ तीन हज़ार रुपये मिलते हैं और वह भी समय पर नहीं। इससे तो गरीबों के बीच असंतोष पनपेगा ही। जब वे यह देखेंगे कि शासक वर्ग के लोग मौज में हैं, अच्छे कपड़े पहन कर बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं; और उनके पास खाने के लिए सूखी रोटी तक नहीं है तो इस स्थिति में उनके घरों के जवान लड़के हथियार उठा लेने को विवश हो जायेंगे।

झारखंड के राज्यपाल महोदय ने उपरोक्त जो बातें कही हैं, सोलहो आने सच हैं। नक्सली कोई शौक से नहीं बनता। जब परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि ज़िंदगी और मौत में से एक को चुनना हो तो कायर लोग़ आत्महत्या कर लेते हैं, पर जिन लोग़ों में जीने की तमन्ना होती है, वे किसी भी स्तर पर संघर्ष करते हैं और अपने प्राणों की रक्षा करने के साथ ही दुश्मनों को चुनौती भी दे देते हैं।

जहां तक राज्यपाल की यह बात कि नक्सली ईमानदार लोग़ों को नहीं मारते, यानी ईमानदार अफ़सरों और पुलिस पदाधिकारियों को भी नहीं मारते, एक आजमाई हुई बात है। वे कोई चोर-लुटेरे और समाजविरोधी तत्व नहीं हैं, वे तो लोग़ों की बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं तो नक्सलियों का शिकार बनने से बचने के लिए उन्हें बेईमानी और भ्रष्टाचार का रास्ता छोड़ कर ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। जब वे वैसा करेंगे तो नक्सली उनके खिलाफ़ कुछ भी नहीं करेंगे।

- प्रतिनिधि